वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के अवसर एवं संभावनाएँ

निर्देशक
डॉ. जी. एस चौहान
प्राध्यापक (अर्थषासत्र)
षासकीय महाविद्यालय कसरावद
जिला खरगोन (म. प्र.)

शोधार्थी
सेवन्ता मुवेल
सहायक प्राध्यापक अर्थषास्त्र
षासकीय महाविद्यालय मनावर
जिला धार

परिचयः–

हमारी भारतीय सभ्यता को प्राचीन काल से चार वर्णो में बाँटा गया था, इनमें से केवल वैष्य ही व्यापार व्यवसाय करता था। उसे मालुम होता था कि उद्यम के समस्त कार्य व लाभ–हानि का जोखिम उसे हि उठाना है। आज समय बदल गया है, प्रतियोगिता के इस दौर में पुरानी सभी मान्यताएँ व अर्थ बदल गये है। आज प्रत्येक व्यक्ति इस दौड़ में षामिल हो रहा है। अब उत्पादन के साधनों को अलग–अलग जगह से एकत्रित करके उद्यम स्थापित करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है। किसी भी देष का विकास वहाँ उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। आज सम्पूर्ण विष्व में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनेक चुनौतियों, समस्याओं एवं संसाधनो के कठिन दौर से गुजर रहा है। भारत एक युवा देष है। यहाँ युवा जनषक्ति अन्य देषो की तुलना में अधिक है। कौषल एक ऐसा साधन है, जो देष के युवाओं को उत्पादक और सषक्त बनाने की क्षमता रखता है। जब हम कौषल विकास की बात करते है तो एक व्यक्ति नही बल्कि पुरे समाज को मजबूत बनाने की बात करते है। यह षक्तिकरण हमारे देष के नागरिको के लिये एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अत्यंत आवष्यक है। श्रम आधारित अर्थव्यवस्था को कौषल–आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना हमारा लक्ष्य है।

उद्यमिता का अर्थ–

व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो, कुछ न कुछ जोखिम निष्चित होती है। उद्यम स्थापित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पता लगाना पड़ता है कि बाजार मे किस प्रकार के माल की कितनी मात्रा में मांग है उसी के अनुकूल माल का उत्पादन करना पड़ता है। तब भी यह निष्चित नही है कि उसे लाभ मिलेगा या हानि होगी, व्यवसाय में यह अनिष्चितता हमेषा बनी रहती है। इन जोखिमों को सहन करने की षक्ति जिस व्यक्ति में होती है उसे हि उद्यमी कहा जाता है। उद्यमी के इन सभी क्रिया–कलापो को ही उद्यमिता कहा जाता है। सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए औद्योगिक नीति एक महत्वपूर्ण अंग है। जुलाई 1991 को नवीन औद्योगिक नीति के बाद 24 सितम्बर 1999 से ऐसे उद्यम लघु एवं सहायक क्षेत्र मे आते है जिनमें 1 करोड़ का निवेष किया गया है। उद्योगो को 2006 में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित होने के बाद दो भागों में बाँट दिया गया है, इस परिवर्तन के बाद अब प्लांट और मषीनरी में निवेष की जगह टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुये प्रधानमंत्री ने इसकी राषि को बढा दिया गया है।

विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र –

1. सूक्ष्म उद्योग जिनमें सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो।
2. लघु उद्योग जिनमें सालाना टर्नओवर 50 करोड से कम हो।

3. मध्यम उद्योग जिसमें सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो।

भारत में 2016–17 में एमएसएमई क्षेत्र में 9.44 प्रतिषत की वृद्धि हुई है। भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई का 45 प्रतिषत योगदान है। मध्य–प्रदेष में 26.74 लाख उद्यमी है जो लगभग 49 लाख लोगो को रोजगार दे रहे है। उद्यमिता विकास को बढावा देने के लिये आज हमारे पास पर्याप्त अवसर है क्योंकि इस महामारी के कारण मजदुर अपने गाँवो की और लोट आये हमे सस्ता, कुषल श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है प्राकृतिक साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो के विकास के लिये इस दिषा में अनेक कार्य किये जा रहे है।

इनकी प्रमुख योजनाएँ निम्न है।

1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
3. कौषल विकास कार्यक्रम
4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
5. डेहरी उद्यमिता विकास योजना
6. कलस्टर विकास कार्यक्रम

अध्ययन का उददे्श्य–

1. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना एवं प्रगति का अध्ययन करना।
2. औद्योगिक विकास में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो का योगदान की स्थिति का अध्ययन करना।
3. सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगो में पूँजी निवेष, रोजगार की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि–

अनुसन्धान कार्य के अध्ययन में द्वितीयक समंको का प्रयोग कर विष्लेषण किया गया है। द्वितीयक समंक वे समंक है जो किसी संस्था द्वारा संकलित किये गये है। और षोधकर्ता किसी उददे्ष्य के लिये संकलित सामाग्री को प्रयोग में लाता है। षोध के अध्ययन में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग म. प्र., सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, सेडमेप भोपाल, आर्थिक समीक्षा भारत सरकार के समंको का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता–

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण स्तर पर इन उद्यमों को मजबूत कर देष की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दे सकते है। इनके संचालन के लिये हमे कुषल उद्यमियों की आवष्यकता महसुस होती है, नये उद्यमियों को प्रेरित करना बहुत जरूरी होता है।ग्रामीण क्षेत्रों में सुक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों को स्थापित करने के लिए महिला और पुरूष उद्यमियों को बढावा देना आज के समय आवष्यक हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लाखो श्रमिक पलायन कर रहे है। इनके पलायन को रोकने का एक मात्र तरीका यह है कि इन क्षेत्रों में छोंटे उद्यमो की स्थापना की जाये जिससे इनको रोजगार तो उपलब्ध होगा ही इनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

आज भारतीय गाँव पहले से ज्यादा सषक्त, सुविधा संपन्न और आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हुए हैं। ग्रामीण युवाओं की कृषि पर निर्भरता पहले से कुछ कम हुई है और ग्रामीण परिवारों की आय में

छोटे स्तर पर निर्माण, मरम्मत सेवाओं की हिस्सेदारी बढी है। आज हमे जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण युवाओं को कौषल प्रषिक्षण उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार और स्वरोजगार को आगे बढाते रहने की आवष्यक्ता है।

तालिका क्रमांक– 1

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से निर्यात– भारत के सकल घरेलु उत्पाद में इन उद्यमों का 29.5 प्रतिषत योगदान है। देष में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है जो निम्न तालिका में दर्षाया गया है।

स.क्र.	वर्ष	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से कुल निर्यात(मिलियन में)	निर्यात का प्रतिशत
1	2012–13	127992	43
2	2013–14	133313	42
3	2014–15	138896	45
4	2015–16	130768	50
5	2016–17	137068	50
6	2017–18	147390	49
	कुल	**815427**	

स्त्रोतः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देष के कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो का हिस्सा बढता गया है। वर्ष 2012–13 में इन उद्यमों से 43 प्रतिषत निर्यात किया गया जो 2016–17 में बढ़कर 50 प्रतिषत हो गया 2017–18 में 49 प्रतिषत 2018–19 में 48.10 प्रतिषत कुल 815427 मिलियन का निर्यात इन उद्यमों से किया गया है। वर्तमान में कोविड 19 के कारण इन उद्यमों का निर्यात सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

तालिका क्रमांक– 2

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों को राजगार प्राप्त

स.क्र.	वर्ष	गाँवों मे रोजगार प्राप्त (लाख में)
1	2014–15	123.19
2	2015–16	126.76
3	2016–17	131.84.
4	2017–18	135.71
5	2018–19	142.03
	कुल	**659.53**

स्त्रोतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2018–19

भारत में 2018–19 में 55 प्रतिषत इकाईयाँ सेवा क्षेत्र में पंजीकृत 45 प्रतिषत विनिर्माण क्षेत्र में पंजीकृत है। देष में सरकार की योजनाओं का 2018–19 में 433520 व्यक्तियों को लाभ मिला है। वर्ष 2014–15 में ग्रामीण क्षेत्र में 123.19 लाख कारीगरों को रोजगार प्राप्त हुआ है जो वर्ष 2018–19 में बढकर 142.03 लाख कुल 659.53 लाख कारीगरों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

तालिका क्रमांक–3

मध्य–प्रदेश में सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगो की स्थापना, निवेश एवं रोजगार

स.क्र.	वर्ष	राज्य में स्थापित इकाईयाँ	राज्य मे पूँजी निवेश (करोड़ मे)	रोजगार
1	2013–14	18660	612.56	44924
2	2014–15	19835	750.00	51571
3	2015–16	48179	6172.75	194761
4	2016–17	87071	9547.32	363812
5	2017–18	206142	14401.67	596990
6	2018–19	297595	19284.97	1030084
	कुल	**677482**	**50769.27**	**2282142**

औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य–प्रदेष का भारत में दसवाँ स्थान है। वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर तक 297595 सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो की स्थापना हुई जो वर्ष 2017–18 में स्थापित उद्योगो 206142 से 44.36 प्रतिषत की वृद्धि हुई है जबकी 2013–14 में 18660 इकाईयाँ स्थापित थी। सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूँजी निवेष वर्ष 2018–19 मे महा दिसम्बर में 19284.97 करोड़ रूपये का पूँजी निवेष इन उद्यमों में किया गया जो वर्ष 2017–18 में निवेषित 14401.67 से 34 प्रतिषत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013–14 में मात्र 612.56 करोड़ रूपये का निवेष किया गया है। वर्ष 2013–14 में म.प्र मे मात्र 44924 व्यक्तियों को सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो में रोजगार मिला है जो 2018–19 में बढकर 1030084 को रोजगार मिला वर्ष 2017–18 में 596990 से 72.54 प्रतिषत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018–19 तक कुल स्थापित इकाईयाँ 677482 निवेष 50769.27 करोड़ रोजगार 2282142 व्यक्तियों को मिला हैं ।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम–

राज्य सरकारों द्वारा अनेक स्थानो पर प्रषिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिसके माध्यम से व्यक्तियों को उद्यमों, स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की आवष्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। उद्यमिता प्रषिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित व्यक्तियों की जानकारी निम्न तालिका में दर्षायी गई है।

तालिका क्रमांक–4

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम– म. प्र. में उद्यमिता विकास को बढाने के लिये इच्छुक उद्यमियों को प्रषिक्षण दिया जा रहा है जिससे लाभान्वित व्यक्तियों की स्थिति इस प्रकार है।

स. क्र.	वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	लाभान्वित व्यक्ति
1	2011–12	79	2464
2	2012–13	104	3199
3	2013–14	347	10491
4	2014–15	269	8070
5	2015–16	115	3240
6	2016–17	169	4732
	कुल	1083	32196

स्त्रोतः–सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग म.प्र. 2016–17

उद्यमियों को कुषल बनाने के लिए 2011–12 में 79 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमे 2464 व्यक्ति लाभन्वित हुये है। वर्ष 2016–17 में 169 कार्यक्रमों से 4732 व्यक्ति लाभन्वित हुये कुल 1083 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में 32197 व्यक्तियों को प्रषिक्षित किया गया है।

उद्यमों में अवसर–

वर्तमान में प्रधानमंत्री ने स्वदेषी को बढावा देने के लिए एमएसएमई उद्यमों को राहत पैकेज देकर उनको बने रहने का भरोसा दिलाया है। कोरोना संकट इन उद्यमों के लिए आपदा के साथ अवसर बनकर भी आया है। महामारी की षुरूआत में भारत में मास्क और पीपीई किट का नाम मात्र का उत्पादन होता था जो आज हर रोज तीन–तीन लाख से अधिक मास्क और पीपीई किट का उत्पादन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत षहरों तक सिमित नही गाँव–गाँव तक पहुँचना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे–छोटे उद्योग षुरू कर अनेक लोगो को रोजगार मिल सकता है। हाल हि में कुछ संस्थाएँ महिलाओं को लेकर छोटे उद्योग चला रही है इन उद्यमों को सरकार की और से राहत भी दिया जा रहा है। इस संकट में प्रवासी मजदूर अपने गाँवो में आ गये लेकिन इनको काम नही मिल रहा है ऐसे में इन उद्यमों को स्थापित कर उद्यमी को कुषल श्रमिक भी मिल जायेंगे और श्रमिको को रोजगार भी उपलब्ध हो जायेगा। लाकडाउन खत्म होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे बढने लगी है। उद्योग संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार करीब 57 प्रतिषत उद्योगो में 50 प्रतिषत से अधिक क्षमता से काम षुरू हो गया है। अनलाक होने से आर्डर बुक, निर्यात, नकदी प्रवाह, और आपूर्ति श्रंखलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है।

युवाओं को कुषल बनाने और फिर उन्हे नया काम देने पर तेजी से काम हो रहा है। पाँच वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए कौषल कार्यक्रमो की और ध्यान देते हुए स्किल इंडिया मिषन की षरूआत की थी। आज एक करोड़ से अधिक लोग सालाना स्किल इंडिया मिषन से जुड़ रहे है। प्रधानमंत्री कौषल विकास योजना के अंतर्गत देष में 92 लाख से अधिक लोगो को प्रषिक्षण दिया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 116 जिलों में बड़े पैमाने पर स्किल मैपिंग कार्यक्रम षुरू किया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना महामारी के कारण वापस आये श्रमिको को अपने गाँवों मे ही रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं से यह आकांक्षा की जा रही है, कि नौकरी पाने की अपेक्षा नौकरी देने की मानसिकता के साथ काम करें। लाकडाउन में म.प्र. के युवा किसान ने अपनी सूझबूझ से निकाली उद्यम की राह, हजारो किसानो ने निराष होकर टमाटर को सड़को पर फेंक दिया है, कुछ किसानो ने लाकडाउन के चलते गाँवो में बेचा लेकिन म.प्र. के धार जिले के एक युवा किसान ने इस नाउम्मीद को अवसर में बदल दिया। इस दौरान उसने 10 टन टमाटर को फेंकने की बजाय पाउडर में बदलकर लाभ कमाया है। ऐसे कंही किसान है जिन्होने आम, हल्दी, अदरक के लिए अवसर तलाष कर अपने कच्चे माल को निर्मित माल में बदल दिया है। जरूरी नही है कि बड़े उद्योग ही लगाए जाए छोटा सा प्रयास हमें सफल बना सकता है।

कोविड–19 महामारी से लड़ने में आईटीआई संस्थानो को भी आगे बढाने का प्रयास किया जा रहा है। लॉ–कास्ट रोबाट, एरोसॉल, फेसषील्ड, स्वैब टैस्टिंग के लिए मोबाईल क्यूबिल, यूवी सेनिटाईजर बनाए जा रहे है। इस समय भारत के पास एक ऐसी कौषल आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का अवसर है, जो देष के लिए लाभदायक होगा। आज का युवा कौषल देषहित में अपना योगदान देगा और एक नया भारत बनाऐंगे, जिसे हम आत्मनिर्भर भारत कहेंगे।

संभावनाएँ–

स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात लघु एवं कुटीर उद्योगो के महत्व को स्वीकार किया गया है, तब से हि सरकार ने इन उद्योगो के विकास के लिए विषेष बल दिया है। भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर

मात्रा में उपलब्ध है यहाँ षिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढती जा रही है जिससे कुषल श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार म.प्र. में साढे सात करोड़ की आबादी मे से 2.34 करोड़ लोग गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन कर रहे है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्यमों की स्थापना कर इनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। मेक इन इण्डिया की सफलता के लिए जरूरी है श्रम और नीति सुधारों को अमल में लाना। विष्वस्तर पर भारत को अपनी पहचान बनाने के लिए भारतीयों को अपनी सोच में परिवर्तन करना पढेगा हमे नोकर नही मालिक बनना है खुद को भी रोजगार मिले और कम से कम चार अन्य लोगो को भी रोजगार मिले तभी भारत को विष्व में अपना परचम फहराने में देर नही होगी।

वर्तमान में देष में एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 633.88 लाख इकाईयाँ है। इसमें सबसे अधिक संख्या सूक्ष्म उद्यमों की है। देष में इन उद्यमों की कुल संख्या 630.52 लाख है,जो 99 प्रतिषत है। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई की 324.09 लाख सूक्ष्म इकाईयाँ 0.78 लाख लघु इकाईयाँ 0.01 लाख मध्यम इकाइयाँ कार्यरत है, जिसमें एस. सी. 15.37 प्रतिषत एस.टी. 6.70 प्रतिषत ओ.बी.सी. 51.59 प्रतिषत जनरल 25.62 प्रतिषत अन्य 0.72 प्रतिषत है। ग्रामीण क्षेत्रों में 51 प्रतिषत और षहरी क्षेत्रों में 49 प्रतिषत इकाईयाँ कार्यरत है। एमएसएमई में 11 करोड़ लोगो को रोजगार मिल रहा है। इनमें से 4 करोड़ 98 लाख के लगभग ग्रामीण क्षेत्र में और 6 करोड़ 12 लाख के लगभग षहरी क्षेत्रों में है। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्यमों की स्थापना कर बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। लघु कुटीर उद्योगो के विकास से खेती में लगे लोगों की बेरोजगारी की समस्या, गॉव से षहर की और श्रम पलायन की समस्या, पूँजी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, महिला रोजगार की समस्या का अन्त होगा और दूसरी तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इससे श्रमिको में भेद मिटेगा और प्रषिक्षण पर होने वाले खर्च में कटौती होगी। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि गाँव षहर बनेगा इन उद्यमों की स्थापना से ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार होने की अधिक संभावनाएँ है जो देष के विकास की और संकेत दे रहे है।

समसयाएँ–

1. **दीर्घकालिक कार्य की कमी**– छोटे उद्यमियों के पास पर्याप्त ग्राहक नही होते है, लागत को कवर करने और आय प्राप्त करने के पर्याप्त कार्य भी उपलब्ध नही होता है।
2. **पूँजी का अभाव**– अधिकांष उद्यमियों के पास स्थायी संपत्ति नही होती है जिसके कारण उद्यम मे निवेष के लिये बड़ी मात्रा में ऋण भी प्राप्त नही कर पाते है।
3. **आधुनिक तकनीक** का अभाव– उद्यमियों के पास नई तकनीकी क्षमताओं की कमी है जिसके कारण वे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नही कर पाते है।
4. कुषल श्रमिको का अभाव– उद्यमियों को कुषल श्रमिक न मिलने के कारण वे नवाचार के प्रति अनिच्छा रखते और पारम्परिक उत्पादों का ही उत्पादन करते रहते।
5. **बाजार का अल्प ज्ञान**– ग्रामीण उद्यमियों में षिक्षा का अभाव होने के कारण बाजार की पूर्ण जानकारी नही होती है।
6. बाजार में बढती प्रतिस्पर्धा– ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ बडे उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सामने टिक नही पाते है।

सुझाव–

1. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु ऋण के संदर्भ में बैंको के लिए पूँजी मानदंडो को और षिथिल बनाया जाना चाहिए।

2. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो के लेन–देन को डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. जहाँ तक संभव हो बडे और लघु उद्योगो में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास को बढावा देने के लिये इन उद्योगो से संबधित व्यक्तियों के लिये उचित प्रषिक्षण की व्यवस्था की जाना चाहिए।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगो की उत्पादन क्षमता बढाने और किस्म सुधारने के लिये अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित किये जाना चाहिए।
6. सुक्ष्म, लघु उद्यमो द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्षन बड़े नगरों तक सीमित न रखकर देष के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष–

भारत एक विकासषील देष से विकसित देष बनने की दोड़ में कृषि आधारित उद्योगो को पिछे छोड़ता जा रहा है। छोटे उद्योग ग्रामिण अर्थव्यवस्था की रीड़ कहे जाने वाले आज बीमारी के षिकार हो रहे है। उद्योग विभाग द्वारा जो कदम उठाये जा रहे है किन्तु कुषल उद्यमी न होने से उनके संचालन में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। मध्य–प्रदेष को उद्योगो का कुषल प्रदेष माना जाता है लेकिन यहाँ भी हालात बिगड़ते जा रहे है। राज्य में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन उद्योगो की स्थापना अति आवष्यक है। एमएसएमई के लिए सरकार की और से 3 लाख करोड़ की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना प्रारम्भ करने के बावजूद उद्यमियों को मिलने वाला कर्ज बढने की बजाए कम होता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आकड़ो के अनुसार जून 2019 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को वितरित कुल कर्ज 3.66 करोड़ मार्च 2020 में बढकर 3.81 करोड़ हो गया जो जून 2020 में घटकर 3.52 करोड़ रह गया। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अधिकांष एमएसएमई कर्ज लेने से बच रहे है इसी कारण इनके कर्ज में कमी आ रही है। राज्य में अनलाक के दौरान लागत ज्यादा, मांग कमजोर और तरलता की कमी उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो का विकास राज्य के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।

सन्दर्भ–

1. डॉ. विष्वकर्मा यू.सी., डॉ. आचार्य आर. के ''उद्यमिता विकास '' श्री विनायक पब्लिकेषन्स आगरा।
2. डॉ. जे. सी. पन्त,. जे. पी. मिश्रा '' अर्थषासत्र '' साहितय भवन पब्लिकेषन्स आगरा।
3. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान
4. आर. बी. आई. और प्रेस सूचना ब्यूरो।
5. प्रषासकीय प्रतिवेदन, मध्य–प्रदेष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 ।
6. भारत सरकार का पोर्टल ।
7. मध्य–प्रदेष षासन का विभागीय पोर्टल।
8. आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 ।
9. प्रतियोगिता दर्पणः–भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योग
10. राष्ट्रीय सर्वे रिपोर्ट
11. कुरूक्षेत्रः– सषक्त होते ग्रामीण युवा
12. समाचार पत्र